चलेंगे तो उनका फिजिकल परफारमेंस और फाइनैंशियल परफारमेंस हमेशा गड़बड़ी का रहेगा और गड़बड़ी का रहा है और उसके परिणामस्वरूप पूरे ऊर्जा क्षेत्र को सफर करना पड़ रहा है ।

जहां तक रि-स्ट्रक्चरिंग का सवाल है, हम लोगों ने जनवरी, 1993 में स्टेट पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस की थी और उसमें कुछ फैसले लिए थे । उसमें यह बहुत अहम फैसला लिया था कि प्लांट लोड फास्टर बढ़ाया जाए, ट्रांसमीशन डिस्ट्रिब्यूशन लॉसिस कम किए जाएं । उसमें यह भी फैसला लिया था कि जहां तक कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा की दरों का सवाल है, टेरिफ का सवाल है, वह कम से कम 50 पैसा प्रति किलोवाट अगर हो जाए, अब उस पर कुछ राज्यों ने तो अमल किया है, कुछ राज्यों ने अमल नहीं किया है । अध्यक्ष जी, यह कन्करेंट सब्जेक्ट है । उनका अधिकार, उनकी अथारिटी उतनी है जितनी हमारी है । उनके अधिकार क्षेत्र में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते । अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है, वह कर रहे हैं, उनके फाइनैंसिस अच्छे हों । फाइनैंशियल पैरामिटर्स और ऑपरेशनल पैरामीटर्स जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और यह लगातार करते रहेंगे । इस सिलसिले में अगर माननीय सदस्य हमारी कुछ मदद कर सकें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा क्योंकि दिक्कत यह है कि जो दरों का सवाल है, बहुत अहम सवाल है । जो राज्य सरकारें हैं, वह एक नीति निर्धारित करती है अपने लिए कि जहां तक अलग-अलग कायरों का, अलग-अलग एरियाज का, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, एक अलग-अलग रेट हो और उसमें अगर राजनीति आने लगे तो वही होगा जो हो रहा है । यह दरअसल सब मुद्दों का एक मुद्दा है, यह मेरा निवेदन है।

सभापति : सैकिंड सप्लीमेंटरी ।

डा० बापू कालदाते : नहीं । यह पूछ लें ।

श्रीमती कमला सिन्हा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी । मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि यह कन्करेंट सब्जेक्ट है और प्रांतों को इसके बारे में देखना होगा । बात तो सही है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि पूर्वी प्रांतों में से, जहां से ऊर्जा का जो रा-मेटीरियल है कोयला, वह ज्यादा तो पूर्वी प्रांतों से, ही आता है, जैसे बिहार । बिहार से 40 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है और ऊर्जा का उत्पादन दूसरे प्रांतों में है । बिहार तो पावर स्टार्व्ड स्टेट है । उसी तरह से उड़ीसा, बंगाल हैं, पिछले तीन सालों में इनकी उर्जा की खपत गिरी है । तो क्या यह सही है कि पिछले 30—40 सालों में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तहत कारखाने लगाए गए थे, उनका नवीनीकरण नहीं हुआ और केन्द्रीय सरकार ने कोई ऊर्जा का कारखाना वहां लगाया ही नहीं और इसीलिए यह एस०ई०बी० भी बीमार पड़ रहा है और साथ-साथ प्रांत भी पीछे हो रहे है, क्या यह बात सत्य है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : अंशतः सत्य है, अंशतः असत्य है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : पूर्णतः सत्य है ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : ईस्टर्न सेक्टर में इस्टर्न ग्रिड है । ईस्टर्न ग्रिड में हमने बहुत सारे कारखाने लगाए हैं और ईस्टर्न ग्रिड को और दूसरे ग्रिड के मुकाबले में पर्याप्त पावर दी जा रही है । मगर पहला सवाल जो आपने किया, वह बिल्कुल सत्य है कि जहां कोयला होता है वहां कारखाने लगें, ऐसी कोई नीति अभी नहीं है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नयी नीति में हम चाहते हैं कि जहां कोयले की खदानें हों वहां ही कारखाने लगें बल्कि ऊर्जा के कारखाने वहीं लगें । यह बहुत जरूरी है । मैं एक चीज और बता दूं कि इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न और है कि सस्ता कोयला मिल जाए तो पावर का जो ट्रांसमिशन है, वह ज्यादा सस्ता पड़ता है । यही मेरा निवेदन है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

Now Papers to be laid on the Table of the House—Shri Sukh Ram.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Privatisation of Power Plants in Maharashtra

*183. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for privatisation of any major power plant in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the stage at which this proposal stands and by when the final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

News Coverage for various Political Parties

*186. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is definite tilt at present in favour of ruling party in respect of news coverage on Doordarshan and A.I.R. networks;

(b) whether Government have estimated the time given to activities of ruling party, B.J.P. and other political parties in the country on these media during the month of November, 1994;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government propose to issue necessary guidelines for the proportionate coverage of these political parties in news on Doordarshan and AIR; and

(e) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir.

(b) and (c) No, Sir. This information is not kept in a centrally compiled form.

(d) and (e) Guidelines are issued by the Government from time to time. Activities of various political parties are covered in the news bulletins strictly on the basis of their news value and newsworthiness.

Reservation in Allotment of Export Quota

*187. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether pursuant to the spirit of Clause (4) of Article 16 of the Constitution it is the policy of Government to provide for reservation of posts and opportunities in the State services for backward classes and weaker sections of society, and by way of providing self-employment opportunities by extending low-interest loans and credits;

(b) if so, what are the reasons for not granting reservations for the weaker sections including Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the allotment of export quota by the Apparel Exports Promotion Council; and

(c) whether Government have taken note of the fact that with liberalisation of economy job opportunities in 'State' services as contemplated under Act 16(4) are shrinking considerably?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The Garment and Textile Export Entitlement Allotment Policies (Quota Policies) whose primary objective is maximization of the foreign exchange earnings, provides a framework for allocation of garment/textile quotas in a non-discriminatory and transparent manner. The exporting units which are eligible for allocation of quotas, have different types of organisational structures like proprietary concerns, partnerships, private limited companies, public limited companies etc. It is not possible to have a meaningful reservation policy in export quotas. As such, Government have not provided for reservation in favour of weaker sections including Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward classes in the matter of allotment of quotas. Government would examine the possibility of having a meaningful reservation in the export quotas.

Mahila Udhyam Nidhi

*188. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether some financial assistance has been extended for women entrepreneurs on minimum promoters' contribution and equity type of assistance under the 'Mahila Udhyam Nidhi';

(b) if so, the details thereof;

(c) whether new tiny and small scale units (whose cost of project does not exceed Rs. 20 lakhs) excluding margin for long term working capital alongwith working capital under single window scheme has also been introduced;

(d) if so, the details thereof;

(e) the amount allocated and released to Gujarat and Maharashtra under the 'Mahila Udhyam Nidhi Scheme' during the last three years, year-wise: and

(f) the items reserved for these units in the State of Gujarat and Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has been operating Mahila Udhyam Nidhi (MUN) Scheme to provide equity type of assistance to women entrepreneurs for setting up new industrial projects in the Small Scale Industrial (SSI) sector. All new industrial projects in the SSI sector as also service activities which are eligible for finance as per SSI norms and set up by women entrepreneurs are eligible for assistance under the scheme provided the project cost does not exceed Rs. 10 lakhs. Assistance under the scheme is in the form of soft loan to meet the gap in the equity after taking into account the promoters' contribution to the project subject to a maximum of 15% of the project cost. No interest is levied on the soft loan but a nominal service charge of 1% per annum is payable annually. The repayment of assistance under MUN is required to be made in 10 years including a moratorium upto five years.

(c) and (d) SIDBI has been operating Single Window Scheme (SWS) since its inception under which composite assistance for fixed assets and working capital is extended to units in the SSI sector by the same agency. At present, the unit in the SSI sector with total project outlay upto Rs. 50 lakhs are covered under SWS. Apart from new units in tiny and SSI sector, assistance under the scheme can